

प्रेषक,

ओम प्रकाश
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून दिनांक 20 अप्रैल, 2020

विषय: कोरोना वायरस (COVID-19) के रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40/111/2020-DM-I(A), दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों को पुनः प्रारम्भ करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया विषयक।

महोदय,

कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम एवं लॉकडाउन की अवधि में निर्माण कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में लोक निर्माण विभाग के द्वारा राज्य में गतिमान चारधाम सड़क परियोजना निर्माण, कुम्भ मेला-2021 की तैयारियों हेतु सड़क एवं सेतुओं का निर्माण, केन्द्रीय सड़क निधि के कार्य, मार्गों के रखरखाव के कार्य, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वीकृत कार्य, सेतु निर्माण कार्य तथा राज्य योजना/जिला योजना के अन्तर्गत अन्य संचालित कार्यों, जिनकी भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक है, के निर्माण हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 15.04.2020 के क्रम में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) संलग्नानुसार प्रेषित की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना/जिला योजना के अंतर्गत जिन मार्गों की भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत से कम है, उनका कार्य प्रारम्भ करने के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धि होने पर पृथक से दिशा-निर्देश निर्गत किए जायेंगे।

2. अतः इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 40/111/2020-DM-I(A), दिनांक 15 अप्रैल, 2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न- यथोक्त।

अल्पकालिक/संक्षेप

मार्गानुसार

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

महोदय,
अपर मुख्य सचिव।

(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव।

पत्र सं. - 08/30 वन (निमोजन)/2020-21 दि. 21/4/2020

पृ0संख्या: 368(1)/111(3)/2020-01(एन0एच0)/2020 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित तिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता
संघीय/राज्य राजमार्ग
रा.डी.बी. कर्जालु, लोक
निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

(2) समस्त अधीक्षक
अभियन्ता, सिविल/
राज्य राजमार्ग/किर्पी/
रा.डी.बी. कर्जालु, लोक निर्माण
विभाग, उत्तराखण्ड।

संलग्न- गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्माण-निर्देशों की छायाप्रति।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, सचिव, आपदा प्रबन्धन/स्वास्थ्य/गृह, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों को इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी/अल्मोडा।
8. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, देहरादून।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(दिनेश कुमार पुनेता)
अनुसचिव।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

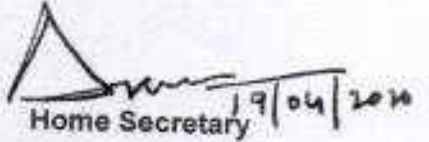
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

No.40-3/2020-DM-I (A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 19th April, 2020

ORDER

In continuation of Ministry of Home Affairs's Orders No.40-3/2020-DM-I(A) dated 29th March, 2020, 15th April, 2020 and 16th April 2020, and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(I) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby issues a Standard Operating Protocol (SOP), for **movement of stranded labour within the State/UT** as **Annexed** herewith, to Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State /Union Territory Authorities with the directions for its strict implementation.


Home Secretary 19/04/2020

To: (As per list attached)

1. The Secretaries of Ministries /Departments of Government of India.
2. The Chief Secretaries/ Administrators of States/Union Territories.

Copy to:

- i) All Members of the National Executive Committee.
- ii) Member Secretary, National Disaster Management Authority.

Standard Operating System (SOP) for movement of Stranded Labour

Due to the spread of COVID-19 virus, workers employed in industry, agriculture, construction and other sectors have moved from their respective places of work, and are housed in relief/ shelter camps being run by State/ UT Governments. Since additional new activities, outside the containment zones, have been permitted in the consolidated revised guidelines with effect from 20th April 2020, these workers could be engaged in industrial, manufacturing, construction, farming and MNREGA works. In order to facilitate their movement within the State/UT, the following guidelines may be followed:

- i. The migrant labourers currently residing in relief/ shelter camps in States/ UTs should be registered with the concerned local Authority and their skill mapping be carried out to find out their suitability for various kinds of works.
- ii. In the event, that a group of migrants wish to return to their places of work, within the State where they are presently located, they would be screened and those who are asymptomatic would be transported to their respective places of work.
- iii. ***It may be noted that there shall be no movement of labour outside the State/UT from where they are currently located.***
- iv. During the journey by bus, it would be ensured that safe social distancing norms are followed and the buses used for transport are sanitized as per the guidelines of the Health authorities.
- v. The National Directives for COVID-19 Management issued under the consolidated revised guidelines dated 15th April 2020 shall be strictly followed.
- vi. The local authorities shall also provide for food and water etc., for the duration of their journey.

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-03
संख्या-370/III(3)/2020-01(एन0एच0)2020
देहरादून : दिनांक १ अप्रैल, 2020

कार्यालय आदेश

कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 29.03.2020, दिनांक 15.04.2020 एवं दिनांक 16.04.2020 के द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये आदेशों के क्रम में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-367/III(3)20-01(एन0एच0)2020 दिनांक 20.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-368 दिनांक 20.04.2020 द्वारा लोक निर्माण विभाग के घट्यनित कार्या हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओपी0) निर्गत की गयी है।

2. उपरोक्त के क्रम में देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में असहाय/फंसे हुए श्रमिकों के आवागमन हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 19.04.2020 में राज्य के अन्दर श्रमिकों के आवागमन/संचरण हेतु निम्न Standard Operating System (SOP) for movement of stranded labour निर्गत किया गया है :-

1. The migrant labourers currently residing in relief/shelter camps in States/UTs should be registered with the concerned local Authority and their skill mapping be carried out to find out their suitability for various kinds of works.
2. In the event, that a group of migrants wish to return to their places of work, within the State where they are presently located, they would be screened and those who are asymptomatic would be transported to their respective places of work.
3. It may be noted that there shall be no movement of labour outside the State/UT from where they are currently located.
4. During the journey by bus, it would be ensured that safe social distancing norms are followed and the buses used for transport are sanitized as per the guidelines of the Health authorities.
5. The National Directives for COVID-19 Management issued under the consolidated revised guidelines dated 15th April, 2020 shall be strictly followed.
6. The local authorities shall also provide for food and water etc. for duration of their journey.

3. लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रही विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जनपदों के जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर stranded labour के उपयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार के उक्त Standard Operating System (SOP) का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।



संख्या- 370(1) / III(3) / 2020-01 (एन0एच0) 2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, स्वास्थ्य/गृह, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि कृपया उक्त कार्यालय आदेश में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों को इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायू।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया भारत सरकार के उक्त दिशा-निर्देशों को समस्त निकायों में परिचरित कर आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने हेतु।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
11. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।